बीज स्वराज अभियान, मध्यप्रदेश

ऐपेक्स ऐवेन्यू, मोती मस्ज़िद के पीछे, रेतघाट, भोपाल

संपर्क : 08718082223, 09425384555

जीनान्तरित बीजों की प्रासंगिकता : एक विमर्श

20 सितम्बर, 2016

कबीर कक्ष, गांधी भवन, भोपाल

जीनान्तरित बीजों की प्रासंगिकता : एक विमर्श

20 सितम्बर, 2016 : कबीर कक्ष, गांधी भवन, भोपाल

जीनान्तरित बीजों की प्रासंगिकता को लेकर कबीर कक्ष, गांधी भवन, भोपाल में प्रदेश के बुद्धिजीवी, चिंतक, कृषि विशेषज्ञ, जैविक कृषक, किसान नेता, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकताओं की परिचर्चा आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश के लगभग 15 जिलों के 40 लोग सम्मिलित हुए।

श्री निलेश देसाई (बीज स्वराज अभियान) :

परिचर्चा की शुरूवात करते हुए बीज स्वराज मंच के श्री निलेश देसाई ने मध्यप्रदेश की स्थितियों एवं जीनान्तरित बीजों के प्रवेश को लेकर प्रदेश में विगत वर्षो में किए गए कार्यो की जानकारी देते हुए कहा कि बीज स्वराज मंच हमेशा से ही जीनान्तरित बीजों के खिलाफ है। आपने कहा कि हम विकास एवं नई तकनीक के खिलाफ नहीं है वरन हम चाहते है कि इस विषय पर खुली चर्चा हो और जीनान्तरित बीजों के अनुमोदन को लेकर चलाई जा रही प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हो। यदि यह इतना ही अच्छा है तो जीईएसी इसे लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरत रहा है। जीएम सरसों को लेकर किए गए परिक्षणों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। खाद्य में जीएम बीजों के प्रयोग से कई हानिकारक दुष्परिणाम सामने आयेगे।

श्री कपिल शाह (ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डियॉ) :

जीएम बीज एवं इससे जुडी तकनीकी जानकारी देते हुए आपने कहा कि जीएम बीज आने से हमारे देशज बीज खत्म हो जाएगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वापसी नहीं हो सकती। विस्तार से इस सारे परिदृश्य पर स्लाइड शो के माध्यम से तथ्यात्मक जानकारी एवं आंकडे प्रस्तुत करते हुए आपने बताया कि जीएम तकनीक असुरक्षित जीन संशोधित करने की तकनीक जीवित प्राणियों को पैदा करने का एक अप्राकृतिक तरीका है जो सटीक भी नहीं है। इस बात के काफी वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध हैं कि यह एक अस्थिर, अप्रत्याशित, अपरिवर्तनीय (जिस को वापिस करना संभव नहीं) और बेकाबू तकनीक है। पर्यावरण में जीएम फसलों का प्रवेश होने से खेती का जोखिम बढ़ता है, किसानों और उपभोक्ताओं के

लिए गैर–जीएम फसलों के विकल्प नहीं रहते और बाजार पर एकाधिकारी ताकतों का कब्जा हो जाता है।

श्री राकेश दीवान (वरिष्ठ पत्रकार) :

परिचर्चा में अपने विचार रखते हुए आपने कहा कि जिस तरह से अधिक उत्पादन का स्वप्न दिखाकर जीएम बीज लाने की तैयारी की जा रही है वह ठीक नहीं है। जबकि हमारे देश में ही इससे अच्छे व गुणकारी बीज उपलब्ध है। इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। इसका समाधान समाज की एकजुटता एवं संयुक्त प्रयासों में समाहित है। और समाज में जागरूकता लाने के ऐसे प्रयास हमें मिलकर करने चाहिए। अगर उद्देश्य अच्छा व सामाजिक हित का हो तो संसाधन स्वयं ही बनते जाते है।

श्री सचिन जैन (भोजन का अधिकार अभियान) :

जीएम बीज ना सिर्फ हमारी कृषि वरन हम सब के लिए अवांछनीय है। यह ना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था वरन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। जीएम सीड के अनुमादन पर आपत्ति व्यक्त करने की डेड लाईन का जिक्र करते हुए आपने कहा कि हमे उस पर अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा और भी कई तरीके है जिसके माध्यम से हम समाज को प्रेरित कर सकते है।

अनिल कर्णे (बीज स्वराज मंच) :

परिचर्चा का समापन करते हुए आपने कहा कि जीए बीज से संबंधित जानकारियों को सरकार एवं नियामकों द्वारा छुपाया नहीं जाना चाहिए। परीक्षण रिर्पोट अंग्रेजी में इंटरनेट पर है उसे हिन्दी में समाज के सामने रखी जानी चाहिए। जिससे समाज अपनी राय कायम कर सके।

परिचर्चा में श्री राजेश भदोरिया, प्रेमेल गुप्ता, तपन जी, सत्यम पाण्डेय, शिव कुमार, सुश्री शिवानी, अनिल भवरे, जगदीश भाई आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

परिचर्चा का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि अनुमोदन की प्रक्रिया में जीएम सरसों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया की समय सीमा जो कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो रही है। उससे पहले संबंधित फोन नम्बर पर स्वयं एवं साथियों के साथ अधिकतम मीस्ड कॉल करेंगे एवं जीए बीज के खिलाफ अपने अपने स्तर पर जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगें।

जीनान्तरित बीजों की प्रासंगिकता : एक विमर्श
बीज स्वराज अभियान, मध्यप्रदेश

www.facebook.com/hindustantimes www.twitter.com/httweetz DOWNLOAD OUR iPAD APP www.hindustantimes.com/iPad OUR EDITION ON KINDLE http://read.bt/JS4

hindustantimes

hindustantimes.com

BHOPAL/METRO Vol VII No. 205 Price ₹ 3.00 16 pages, including four pages of HT City

THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2011

NEW YORK, NEW JERSEY 'BOMBER' RAHAMI INSPIRED BY BIN LADEN, SAYS US ›ht world p10

JOBS GALORE IN E-COMMERCE ›ht business p11

INDIANS TO HUNT KIWIS IN HISTORIC MATCH A LONG 13-MATCH HOME SEASON KICKS OFF IN KANPUR TODAY ›ht sport p12

Don't give go ahead to GM mustard, farmers and activists tell govt

Neeraj Santoshi
neeraj.santoshi@hindustantimes.com

BHOPAL: Farmers and activist groups in Madhya Pradesh have asked the government not to give its approval for genetically modified mustard fearing a threat to the organic variety which is produced in large quantity in the state.

In a letter written to environment minister Anil Dave on Tuesday, representatives of over two dozen farmer groups and those promoting organic farming sought disclosure of all safety documents on GM Mustard.

The opposition comes after the safety document prepared by the sub-committee of Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) was put up on the environment ministry's website on September 5, inviting comments within a month.

"The government can't force people to eat GM mustard," the letter said, asking the minister not to give approval for GM Mustard.

"What is the need to introduce GM mustard when everyone already knew the fate of Bt cotton?" they asked.

Kapil Shah, national secretary of Organic Farmers Association of India, told HT that only after people go though the documents would they be in a position to comment.

"We are demanding at least three months time to make comments. We also want disclosure of all the safety dossiers on the GM Mustard," he said.

Shah said 15 years of Bt cotton cultivation in India had exposed GM technology as the insects, which Bt cotton was supposed to defy, developed resistance, and farmers were using more pesticides than ever before on cotton crops.

"Farmers and their representatives with whom I interacted here are very sceptical about GM mustard, as it is a food crop," he said, adding that there are other means to ensure better yield and improve the crop.

Madhya Pradesh is the fourth major state producing mustard with a share of nearly 11% to the country's total mustard production.

Neelesh Desai state convener Beej Swaraj Abhiyan said the state has been in the forefront of promoting organic farming.

"GM mustard has the potential to push local seed varieties to the background, increase monopoly of a particular seed variety and its suppliers. Also, we have no idea about its long term impact," he argued.

In the past, Madhya Pradesh has strongly opposed introduction genetically modified technology, with the then state agriculture minister Ramkrishna Kusmaria, an agricultural doctorate, submitting a book he authored on dangers of 'Genetically Modified Organisms' to the members of the parliament in 2010, arguing that GM foods in the long run will end the autonomy of farmers and make them dependent on monopolized supply sources.

Farmers with whom HT spoke said they were not being informed about what could happen with the use of GM Mustard in the long run.

Laxman Singh Muniya from Jhabua questioned as to why the government can't improve local seed varieties.

Another farmer Jagdish Yadav from Rewa district said they were apprehensive about its long-term impact on the health of people. "Manipulating crops like this, playing with nature can be dangerous. We don't need to take this risk, especially when we have to eat it," he said.

STORY BEHIND THE GM MUSTARD

- India's apex regulatory body on genetically modified organisms — Genetic Engineering Approval Committee — uploaded a document called 'Assessment of Food and Environmental Safety' on environment ministry's website on September 5.
- It invited comments for the proposal on authorisation of environmental release of genetically engineered Mustard (Brassica juncea) hybrid DMH-11.
- At present, only GM cotton is cultivated in India.
- Earlier, during the UPA regime, then environment minister Jairam Ramesh placed a moratorium on the commercialization of Bt Brinjal after activists and farmers opposed it.
- If the environment ministry gives a go ahead for GM Mustard, it will be the first GM food crop to be commercially cultivated in the country
- The GM mustard (DMH-11) was developed by the Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants, Delhi University.